

सामान्या कणवधाटी

RNI No.: UTTHIN/2013/54659

वर्ष-13 अंक-20 हरिद्वार, मंगलवार, 01 सितम्बर, 2026 मूल्य-दो रूपया मात्र पृष्ठ-8

व्यापारी और उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ : मुख्यमंत्री



हल्द्वानी । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राष्ट्रीय खेल दिवस कार्यक्रम के उपरांत आईटीसी फॉर्च्यून, हल्द्वानी में आयोजित संवाद कार्यक्रम में कुमाऊं मंडल के व्यापारियों, उद्योग प्रतिनिधियों एवं विभिन्न व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों की समस्याओं, सुझावों एवं अपेक्षाओं को सुना और राज्य सरकार की ओर से उनके समाधान के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

संवाद के दौरान व्यापारियों एवं उद्योग प्रतिनिधियों ने जीएसटी से संबंधित प्रक्रियाओं के सरलीकरण, मंडी शुल्क, अतिक्रमण एवं पार्किंग की समस्या, लीज नवीनीकरण, औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के

विस्तार, स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने तथा युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने सहित विभिन्न विषय मुख्यमंत्री के समक्ष रखे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारी और उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। व्यापारी न केवल रोजगार सृजन करते हैं, बल्कि उत्पादन और उपभोक्ता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में राज्य की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े उद्यमी तक प्रत्येक व्यापारी प्रदेश की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण भागीदार है। राज्य सरकार व्यापारियों एवं उद्यमियों के हितों के प्रति संवेदनशील है और उनके लिए सुरक्षित, पारदर्शी तथा सरल

व्यावसायिक वातावरण तैयार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड जैसे चुनौतीपूर्ण समय में भी प्रदेश के किराना एवं रिटेल व्यापारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों तक राशन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई। संकट के समय व्यापारी वर्ग ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर यह सिद्ध किया कि वह देश और प्रदेश का मजबूत स्तंभ है। उन्होंने कहा कि हमारे व्यापारी 'ब्रांड इंडिया' के सच्चे राजदूत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश में व्यापार, उद्यमिता और नवाचार के प्रति नया विश्वास पैदा हुआ है। प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है कि देश में ऐसा वातावरण तैयार हो, जिसमें सामान्य परिवार का युवा भी नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनने का सपना देख सके। केंद्र एवं राज्य सरकार इसी सोच के साथ युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को प्रोत्साहित कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड में 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' को और अधिक सरल एवं प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। निवेशकों एवं उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 'निवेश मित्र' की व्यवस्था की गई है और सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत किया गया है।

कुंभ मेले में आने वाले यात्रियों का स्वागतम् से होगा सत्कार

हरिद्वार। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत को जन-जन तक पहुंचाने और प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को देश-दुनिया के सामने रखने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल शुरू करने की तैयारी की है। आगामी कुंभ के दौरान धर्मनगरी हरिद्वार और तीर्थनगरी ऋषिकेश में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों का स्वागत संस्कृत भाषा के शब्दों और श्लोकों से किया जाएगा। अब यात्रियों के स्वागत में 'वेलकम' की जगह स्वागतम् जैसे संस्कृत शब्द सुनाई देंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत हरिद्वार और ऋषिकेश को संस्कृत नगरी के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य कुंभ जैसे वैश्विक धार्मिक आयोजन के माध्यम से संस्कृत भाषा की व्यापक पहचान बनाना है। उत्तराखंड संस्कृत संस्थान के सचिव प्रो. विनय कुमार विद्यालंकार ने बताया कि उत्तराखंड संस्कृत संस्थान मूल ही 100 से अधिक लोगों को संस्कृत भाषा का प्रशिक्षण देने जा रहा है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में रेलवे स्टेशन के कुली, ऑटो चालक, टैक्सी चालक, बस कंडक्टर समेत आम लोगों को शामिल किया जाएगा। इन्हें कुंभ के दौरान यात्रियों

से बातचीत में इस्तेमाल होने वाले सामान्य शब्दों और वाक्यों का संस्कृत में प्रयोग करना सिखाया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोग देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों से संस्कृत के सामान्य शब्दों में संवाद कर सकेंगे। इसके लिए अलग-अलग वर्गों के लोगों को हर माह प्रशिक्षण दिए जाने की योजना है।

कुंभ में संस्कृत के अधिकाधिक प्रयोग से उत्तराखंड की प्राचीन संस्कृति और भाषा का संदेश देश विदेश तक पहुंचेगा। हरिद्वार और ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, टैक्सी एवं ऑटो सेवाओं से जुड़े लोगों द्वारा संस्कृत में यात्रियों का स्वागत किए जाने से प्रदेश की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान भी सामने आएगी। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। इस का संदेश भी देश दुनिया में जायेगा। सबसे पहले हरिद्वार के कुलियों से भी इसकी शुरुआत की जाएगी। हरिद्वार के कुलियों ने भी सरकार की इस पहल का स्वागत किया। किशन सिंह, अध्यक्ष कुली संगठन ने बताया कि सरकार जो अभियान चला रही है, उसे सीखेंगे और हरिद्वार आने वाले यात्रियों का स्वागतम् करके ही स्वागत किया जाएगा।

जनसुनवाई में 44 शिकायतें दर्ज, 26 का मौके पर निस्तारण

हरिद्वार । जिला कार्यालय सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जनसुनवाई हुई। इसमें विभिन्न विभागों से जुड़ी 44 शिकायतें सामने आईं, जिनमें से 26 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजकर समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई में राजस्व, भूमि विवाद, बिजली, अतिक्रमण, जलभराव, पेयजल और राशन कार्ड से जुड़ी समस्याएं उठीं।

औरंगाबाद निवासी योगेंद्र कुमार ने नाली निर्माण और जल निकासी, सुमन नगर निवासी कमलेश उप्रेती ने जलभराव की समस्या के समाधान की मांग की। वहीं, प्रमोद कुमार ने मकान निर्माण में पड़ोसियों द्वारा बाधा डालने, ओमकार ने सौर ऊर्जा संयंत्र के ऋण व व्याज माफ करने और कमलेश ने मंदिर के पास संचालित शराब की दुकान बंद कराने की मांग की। पुरनपुर साल्हापुर निवासी बबीता ने बारिश से क्षतिग्रस्त मकान के लिए आर्थिक सहायता मांगी। डीएम ने अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता और समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने

के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जरूरत पड़ने पर अधिकारी मौके पर जाकर समस्या का समाधान करें। बैठक में जिला विकास अधिकारी कमलेश कुमार पंत, मुख्य शिक्षा अधिकारी अमित कुमार चंद, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी, जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत, डीपीआरओ मुस्तफा खां, अधिशासी अभियंता यूपीसीएल दीपक सैनी, उप नगर आयुक्त दीपक गोस्वामी आदि मौजूद रहे।

सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा: जनसुनवाई के दौरान सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की भी समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. लालित नारायण मिश्र ने अधिकारियों को लंबित शिकायतों का गंभीरता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने 36 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता से निस्तारित करने को कहा। समीक्षा में एल-1 स्तर पर 413 और एल-2 स्तर पर 120 शिकायतें लंबित मिलीं। अधिकारियों को इनका शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

हरिद्वार में 12 उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र बदले, एसएसपी ने जारी की तबादला सूची

हरिद्वार । जिले की पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने 12 उपनिरीक्षकों एवं सहायक उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। तबादला आदेश के तहत कई चौकी प्रभारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को थानों और कार्यालयों में भेजा गया है।

तबादला सूची के अनुसार एसआई मनोज रावत को श्यामपुर थाने से कोतवाली रुड़की भेजा गया है। एसआई संजीत कंडारी को चौकी हर की पौड़ी से स्थानांतरित कर एसएसआई श्यामपुर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं एसआई अंशुल अग्रवाल को कोतवाली रानीपुर से हटाकर चौकी प्रभारी हर की पौड़ी बनाया गया है।

इसी क्रम में एसआई उमेश कुमार को चौकी शांतशाह से हटाकर चौकी प्रभारी लखनौता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसआई देवेंद्र पाल को बजाज चौकी से स्थानांतरित कर थाना कनखल भेजा गया है। एसआई समीर पांडे को रेल चौकी से स्थानांतरित कर बाजार चौकी लक्सर का प्रभारी बनाया गया है।

एसआई अमित नौटियाल को कनखल से स्थानांतरित कर चौकी प्रभारी इमलीखेड़ा की जिम्मेदारी दी गई है। एसएसआई प्रमोद सिंह को पुलिस लाइन से सीओ सिटी कार्यालय भेजा गया है, जबकि एसएसआई युवराज को सीओ सिटी कार्यालय से स्थानांतरित कर थाना बुग्गावाला भेजा गया है।

इसके अलावा एसआई अजय को चौकी लखनौता से हटाकर चौकी प्रभारी शांतशाह बनाया गया है। एसआई विपिन कुमार को लक्सर बाजार चौकी से स्थानांतरित कर प्रभारी चौकी रेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं एसआई पुष्कर चौहान को कनखल से



स्थानांतरित कर बाजार चौकी ज्वालापुर का प्रभारी बनाया गया है।

पुलिस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में किए गए इस फेरबदल को जिले में कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है।

नईपी-2020 के संदर्भ में हिंदी अध्ययन की नई दिशाओं पर होगा मंथन

हरिद्वार । राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में हिंदी भाषा और साहित्य के अध्ययन की नई दिशाओं पर गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय में मंथन होगा। विवि के हिंदी विभाग एवं शोध एवं विकास प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और हिंदी भाषा-साहित्य अध्ययन की नई दिशाएं' विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। संगोष्ठी महर्षि दयानंद सभागार, संस्कृत विभाग में हाइब्रिड माध्यम से होगी।

सम्पादकीय



ट्रंप काल में कई बातें उजागर

अडानी धन की ताकत से वे अमेरिका में भी बरी हो गए हैं। मगर इस क्रम में यह भी साफ हुआ है कि अमेरिकी न्याय व्यवस्था कैसे काम करती है और उस पर धन का कितना प्रभाव है। अमेरिकी जिला न्यायाधीश निकोलस गरौफिस ने अडानी समूह के खिलाफ घूस देने और धोखाधड़ी के आपराधिक मुकदमे को खारिज करने पर यह कहते हुए सहमति दे दी कि 'संघीय अभियोजकों के निर्णय की समीक्षा करने का जज के पास सीमित अधिकार' है। लेकिन उन्होंने डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन के न्याय विभाग के इस निर्णय की कड़ी आलोचना करते हुए लिखा- 'अभियोग खारिज करने के निर्णय में बरती गई अनियमितताएं चिंताजनक हैं।' उन्होंने दो टूक कहा कि न्याय विभाग ने सामान्य से हटकर अलग प्रक्रिया अपनाई। जज ने खासकर न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ट्रेंट मैक्कोटर की आलोचना कड़ी की है। कहा- मैक्कोटर ने विभिन्न संघीय कार्यालयों के अनगिनत अधिकारियों और विशेषज्ञों की पेशेवर राय को नजरअंदाज कर दिया। जज ने बेलाग इस पर रोशनी डाली कि न्याय विभाग ने यह फैसला अडानी के वकीलों के साथ मिलकर लिया, जबकि अमेरिकी जांच एजेंसियों-एफबीआई और एसईसी, इस केस को दर्ज करने वाले अभियोजकों तथा अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय की कोई सलाह नहीं ली गई। जज ने इसे 'अत्यंत असामान्य' बताया है। इससे पहले जब न्याय विभाग ने केस वापस लेने का शुरुआती अनुरोध भेजा, तो जज ने उसे 'कमजोर, सतही और अस्पष्ट' तर्कों पर आधारित बताया था। तब कोर्ट ने न्याय विभाग से मामले को खारिज करने के ठोस कारण मांगे थे। अब अंतिम फैसले में न्यायाधीश ने जो कहा है, उससे साफ है कि न्याय विभाग उन्हें संतोषजनक जवाब भेजने में नाकाम रहा। उसने स्पष्ट नहीं किया कि अडानी समूह के किन शर्तों पर राजी होने के बाद ट्रंप प्रशासन ने उपरोक्त फैसला लिया। इसके पहले अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनियम आयोग द्वारा दर्ज कराए गए के मुकदमे में गौतम अडानी 60 लाख और उनके भतीजे सागर एक करोड़ 20 लाख डॉलर का भुगतान करने पर राजी हुए थे। इस तरह धन की ताकत से वे अमेरिका में भी बरी हो गए हैं। मगर इस क्रम में अमेरिकी न्याय व्यवस्था कैसे काम करती है और उस पर धन का कितना प्रभाव है, यह साफ हुआ है। ट्रंप काल में ऐसी कई बातें उजागर हो रही हैं, जो जिन पर पहले परदा पड़ा रहता था।

तालमेल का अभाव

पंचवर्षीय योजनाओं में लगातार गरीबी उन्मूलन, कृषि विकास की योजनाएं, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, स्कूली एवं कॉलेज की शिक्षा, स्वास्थ्य की तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए बड़ी-बड़ी आर्थिक योजनाएं बनती रही हैं, पर न तो पूरी तरह योजनाओं में अमल हो पाया और ना ही भरपूर वित्तीय संसाधनों का सही-सही समुचित दोहन ही हो पाया। वैसे तो यह कल्पना की गई थी कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत की सरकारें ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देकर शहर तथा गांव की सरहदों को मिटाने का प्रयास करेगी, हमारा लोकतांत्रिक ढांचा इतना समावेशी और मजबूत नहीं हो पाया कि हम देश के संपूर्ण विकास के लिए कटिबद्ध हो पाए संसद, विधायिका और कार्यपालिका में तालमेल की कमी के कारण भारत में विकास कल्पना के अनुरूप मूर्त रूप नहीं ले पाया। हमें नवीन भारत की संकल्पना के साथ-साथ गरीबी उन्मूलन प्रयास को बहुत सशक्त एवं दमदार बनाना होगा। केवल गरीबों को मुफ्त में अनाज देकर उनकी गरीबी दूर नहीं की जा सकती है गरीबों को अनाज देने के साथ-साथ उनके हाथों को काम और आजीविका के साधन भी देने होंगे, तब जाकर देश की स्थिति सुधर सकती है हमें गरीबी के अनेक स्वरूपों को जड़ से खत्म करना होगा।

आत्म स्वरूप में पवित्र संकल्पो का पर्व है रक्षाबंधन!

राशि के रंगों के अनुरूप भी बांधते है राखी



रक्षाबंधन की शुभकामनाएं

डॉ श्रीगोपाल नारसन एडवोकेट

परमात्मा हमारी रक्षा करे और हम परमात्म अनुभूति के साथ पवित्रता का संकल्प करते हुए देवता के समान बन सके, यही रक्षाबंधन पर्व की मूल अवधारणा है। सृष्टि में हम सभी परमात्मा की संतान हैं और परमात्मा हमारा परमपिता है। इसी कारण उसकी संतान होने के नाते हम सब आपस में रूहानियत रूप में भाई-भाई या फिर भाई बहन हुए, एक दूसरे को यही हमें मानना और समझना भी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की रक्षा करना भी हम सबका दायित्व है। इसी पवित्र संकल्प को बंधन रूप में मानते हुए रक्षा बंधन पर्व मनाया जाता है। रक्षा बंधन का पर्व हर वर्ष सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस वर्ष रक्षा बंधन का पर्व 28 अगस्त को मनाया जा रहा है। राखी बांधने के लिए बहने राखी की थाली में रोली, कुमकुम, अक्षत, दीपक, मिठाई और राशि के अनुसार रंग वाली राखी रखकर भाई के लिए मंगलकामना करे और तिलक लगाकर राखी बांधे। भाई की राशि मेष है तो इसका स्वामी मंगल है। ऐसे भाई को लाल रंग की राखी बांधना शुभ माना जाता है। इससे उनके जीवन में भरपूर ऊर्जा बनी रहती है। वृष राशि के भाई का स्वामी शुक्र है। बहन अपने भाई को नीले रंग की राखी पहनाएं तो उसके लिए शुभ होगा। मिथुन राशि के स्वामी बुध है। ऐसे में अपने भाई को हरे रंग की राखी बांधे। इससे सुख, समृद्धि और दीर्घायु होते हैं।

कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। इस राशि भाई के लिए पीले या फिर सफेद रंग की राखी सही होगी। इस रंग से आपके जीवन में भरपूर खुशहाली आएगी। सिंह

राशि के स्वामी सूर्य है। ऐसे में अपने भाई के लिए पीले-लाल रंग की राखी खरीदें। उनके लिए सही होगा। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। ऐसे भाई को बहन से हरे रंग की राखी बंधवानी चाहिए। इससे सभी प्रकार के ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। भाई-बहन के बीच प्रेम बना रहता है। तुला राशि के भाई को नीला या फिर सफेद रंग की राखी बांधना शुभ है। इस राशि के स्वामी शुक्र है। वृश्चिक राशि के भाई का स्वामी मंगल है। ऐसे भाई को लाल रंग की राखी बांधना शुभ माना जाता है। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति है। इस राशि के भाई को सुनहरे पीले रंग की राखी बंधवानी चाहिए या फिर पीले रंग की

राखी बांधनी चाहिए। मकर

राशि के स्वामी शनि है। बहन अपने भाई को नीले रंग की राखी बांधनी चाहिए। इससे भाई-बहन का अटूट रिश्ता बना रहेगा। कुंभ राशि के भाई को गहरे हरे रंग की राखी जिसमें रुद्राक्ष हो या फिर रुद्राक्ष माला पहननी चाहिए। मीन राशि के भाई को सुनहरे हरे रंग की राखी बांधनी चाहिए। इसे शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों के लिए पीले रंग की राखी शुभ है।

भाई-बहन का रिश्ता सबसे पवित्र और विश्वनीय है। चाहे बहन हो या भाई दोनों ही एक दूसरे के प्रति शुभ भावना रखते हैं और एक दूसरे की प्रगति सदा चाहते

हैं, वह भी बिना किसी स्वार्थ के। हालांकि रक्षाबंधन पर जब बहन भाई को राखी बांधती है तो भाई बदले में उसे कुछ उपहार देता है। ऐसा इसलिए है ताकि भाई-बहन के बीच प्रेम और सदभाव उत्तरोत्तर बढ़ता रहे और कम से कम एक दिन ऐसा हो जब भाई बहन एक दूसरे से मिलकर मन की खुशी मना सकें। गांव देहात में पंडित द्वारा अपने यजमानों को रक्षासूत्र यानि राखी बांधने का प्रचलन है। इसके पीछे भी यही अवधारणा है कि पंडित को विद्वान और पवित्र माना जाता है और वह रक्षासूत्र बांधने के पीछे अपने यजमान को बुद्धिमान और पवित्र रहने का संदेश

देता है। रक्षाबंधन के पर्व पर जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उन्हें विकारों को त्यागने का संकल्प लेना चाहिए। जिसकी शुरुआत प्रति रक्षाबंधन एक विकार को त्यागने के संकल्प के साथ की जा सकती है। मनुष्य में व्याप्त विकार एक नहीं अनेक होते हैं। जिनमें काम क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार जहां प्रमुख हैं वहीं ईर्ष्या, द्वेष, घृणा जैसे विकार भी मनुष्य की प्रगति में बाधक हैं। सच पूछिए तो रक्षाबंधन है ही पवित्रता का पावन पर्व, जिसमें भाई-बहन के पवित्र रिश्ते की रक्षा के लिए रक्षासूत्र बांधने की वर्षों से परम्परा चली आ रही है। इस पर्व के माध्यम से जहां हम अपनी बहनों की सुख

समृद्धि और प्रगति की कामना करते हैं वहीं बहन भी अपने भाई की दीर्घायु की कामना के साथ-साथ उसकी उन्नति की प्रार्थना करती हैं। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस पर्व को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है। ब्रह्माकुमारी बहनें समाज के शीर्ष पदों पर विराजित महानुभावों से लेकर आमजन तक राखी पर्व का संदेश उन्हें राखी बांधकर देती हैं। वें राखी बांधने के बदले कोई उपहार या नगदी कभी ग्रहण नहीं करती हैं। अपितु चाहती हैं कि जिस भाई को उन्होंने राखी बांधी है वह कम से कम अपने भीतर व्याप्त एक अवगुण का त्याग हमेशा के लिए करें। तभी यह पर्व सार्थक माना जाता है। इस संस्था में रक्षाबंधन पर्व मनाने की शुरुआत 15 दिन पहले से ही हो जाती है और बाद तक चलती रहती है। ताकि समाज अवगुणों से मुक्त हो और एक स्वर्णिम सदुणी समाज की स्थापना हो सके। चूंकि भाई और बहन के रिश्ते से पवित्र दुनिया में कोई भी रिश्ता नहीं होता। इस दिन बहनें अपने भाईयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई जीवनभर उसकी रक्षा का प्रण लेता है। हालांकि मान्यता यह भी है कि सभी दिन परमपिता परमात्मा के बनाये हुए हैं जब परमात्मा की कृपा होती है तो सभी कार्य स्वतः

ही सिद्ध होने लगते हैं। लेकिन फिर भी सनातन धर्म के अनुसार कुछ दिनों का महत्व अलग होता है, जिसे हम त्यौहार या फिर पर्व कहते हैं। जबकि परमात्मा की दृष्टि में सभी दिन एक जैसे ही होते हैं। उनमें विशेष कुछ है तो वह है शुभ और अशुभ लगन। जिसे हम साधारण भाषा में शुभ व अशुभ समय भी कहते हैं। जिसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सभी बहनें अपने भाईयों की कलाई पर शुभ समय में ही रक्षासूत्र को बांधने का प्रयास कर सकें। यह ऐसा पर्व है जिसे कभी भी और किसी भी समय व किसी भी दिन मनाया जा सकता है। आज आवश्यकता भी इसी बात की है, कि समाज में बहनों का सम्मान हो, उनकी रक्षा हो और वें स्वाभिमान के साथ सिर उठाकर निर्भीक जीवन जी सकें। तभी पर्व की सार्थकता सिद्ध हो सकती है।

धामी कैबिनेट की बैठक सम्पन्न, अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगाई गई। धामी कैबिनेट ने राज्य के विकास, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और सहकारिता क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से कई दूरगामी निर्णय लिए हैं। बैठक में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 की तर्ज पर 'उत्तराखण्ड राज्य सहकारिता नीति, 2026' को प्रख्यापित करने का फैसला लिया गया। इस नीति के तहत सात रणनीतिक मिशन तय किए गए हैं, जिनसे ग्रामीण और शहरी इलाकों में पारदर्शी, तकनीक-सक्षम सहकारिता ढांचा खड़ा होगा और युवाओं व महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

पर्यावरण सुरक्षा और राजस्व प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 में बड़ा बदलाव किया है।

अब राज्य में सीएनजी और हाइब्रिड वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। बाजार में इन गाड़ियों की बढ़ती संख्या और उनसे राजस्व पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए इन्हें क्रमबद्ध तरीके से कराधान के दायरे में लाने का निर्णय



लिया गया है। इसके साथ ही, राज्य सरकार के अधीन काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन निर्धारण नियम, 2016 की अनुसूची-1 में संशोधन किया गया है। अब तक उत्तराखण्ड में लेवल-13 के सीधे बाद लेवल-15 और 16 का प्रावधान था, जो केंद्र सरकार के ढर्रे से अलग था। इसे संशोधित करते हुए 1,44,200-2,18,200 रुपये के वेतनमान के लिए लेवल-

15 की जगह लेवल-14 और 1,82,200-2,24,100 रुपये के वेतनमान के लिए लेवल-16 के स्थान पर लेवल-15 कर दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य की क्षमता बढ़ाने के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार की 65 एकड़ जमीन में से 1 एकड़ भूमि को 99 साल की लीज पर मात्र 1 के

सांकेतिक शुल्क पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) नई दिल्ली को देने पर सहमति बनी है। यहां BSL-3 स्तर की प्रयोगशाला स्थापित होगी, जिससे महामारियों की जांच और त्वरित नियंत्रण की क्षमता में अभूतपूर्व बढ़ोतरी होगी।

इसके अलावा, राज्य में औषधियों और मेडिकल उपकरणों की पारदर्शी खरीद के लिए उत्तराखण्ड मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन के गठन और चिकित्सा स्वास्थ्य सांख्यिकीय संवर्ग सेवा नियमावली 2026 को भी हरी झंडी दी गई है। देहरादून में रिस्पना नदी के किनारे अवैध रूप से बसी मलिन बस्तियों के पुनर्वसन के लिए काठबंगला में निर्मित 116 मकानों का आवंटन नगर निगम द्वारा चयनित लाभार्थियों को करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसके अतिरिक्त, यूएसडीए (UUSDA) के संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी देते हुए 94 नए अस्थायी पदों के सृजन पर सहमति बनी है, ताकि कोटद्वार, ऋषिकेश, रुद्रपुर जैसे शहरों में पेयजल और सीवरेज परियोजनाओं का काम तेजी से निपटाया जा सके।

प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण और अन्य सुधारों की कड़ी में घाटे में चल रहे उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि.

(TDC) के 85 कर्मचारियों (तृतीय श्रेणी के 22 और चतुर्थ श्रेणी के 63) को उधमसिंह नगर व आसपास के जिलों के अन्य सरकारी विभागों में अधिकतम 10 वर्षों के लिए सेवा स्थानांतरण पर भेजा जाएगा। वहीं लोकायुक्त खोजबीन समिति नियमावली 2026' को मंजूरी दी गई है। कारागार प्रशासन में उप कारापाल के 25 प्रतिशत पदोन्नति कोटे में 90 प्रतिशत पुरुष प्रधान बंदीरक्षक और 10 प्रतिशत महिला बंदीरक्षक का अनुपात तय किया गया है।

डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत 'उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख सक्रिया नियमावली, 2026' को लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसके माध्यम से जीआईएस और आधुनिक तकनीक से शहरी आबादी क्षेत्रों के सटीक भू-अभिलेख तैयार किए जाएंगे। अंत में, अंत्योदय फाउंडेशन द्वारा ऋषिकेश के वीरभद्र में कैंसर रोगियों के लिए हॉस्पिस केयर सेंटर स्थापित करने हेतु दान में मिली भूमि की गिफ्ट डीड पर स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करने का मानवीय निर्णय भी मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया है।

कलाई पर सजा रक्षासूत्र, SSP दून बोले- हर कदम पर साथ खड़ी है पुलिस



देहरादून । राजधानी के पुलिस कार्यालय और पुलिस लाइन परिसर में रक्षाबंधन का त्योहार बेहद खास और भावुक अंदाज में मनाया गया। पुण्य द एक्सपेरिमेंटल स्कूल और पुलिस मॉडर्न स्कूल के छोटे-छोटे बच्चे जब हाथों में रेशमी धागे और थाली सजाकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) देहरादून प्रमोद डोभाल से मिलने पहुंचे, तो

माहौल आत्मीयता से भर गया। बच्चों के साथ-साथ ब्रह्मकुमारी संस्था की बहनों ने भी पुलिस कार्यालय पहुंचकर एसएसपी को रक्षासूत्र बांधा और उनकी दीर्घायु की कामना की। नन्हे-मुन्हे बच्चों को देखकर पुलिस कप्तान का रुख भी एक अभिभावक जैसा नजर आया। एसएसपी ने सभी बालिकाओं से आत्मीय संवाद कायम किया। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, स्कूली गतिविधियों और उनकी रुचियों के बारे में एक-एक कर जानकारी ली। इसके बाद कप्तान ने बच्चों को गिफ्ट्स सौंपे और उनके उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद दिया। मुलाकात के दौरान ब्रह्मकुमारी संस्था से आई बहनों ने कप्तान की कलाई पर रक्षासूत्र बांधकर समाज में शांति और सुरक्षा की दुआ की। इस मौके पर संस्था की प्रतिनिधियों ने देहरादून पुलिस द्वारा जिले में महिला सुरक्षा, साइबर अपराधों पर अंकुश और मिशन शक्ति के तहत चलाए जा रहे अभियानों की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिस की तत्परता से शहर की महिलाओं और बेटियों में सुरक्षा का अहसास मजबूत हुआ है। जवाब में एसएसपी देहरादून प्रमोद डोभाल ने ब्रह्मकुमारी बहनों और आम नागरिकों को भरोसा दिलाया कि देहरादून पुलिस हर स्थिति में उनकी मदद के लिए तत्पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में किसी भी तरह की आपात स्थिति या सहायता की जरूरत पड़ने पर पुलिस का हर जवान कदम से कदम मिलाकर साथ खड़ा रहेगा। शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के साथ-साथ बेटियों की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

त्योहारों में स्थानीय उत्पादों की खरीद को दें प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

देहरादून । मुख्यमंत्री धामी ने मंगलवार को सचिवालय में सशक्त बहना उत्सव के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टालों से विभिन्न स्थानीय उत्पादों की खरीदारी की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से आगामी त्योहारों में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' के संकल्प को आगे बढ़ाने में सहभागी बनने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की मातृशक्ति द्वारा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से तैयार किए जा रहे उत्पाद हमारी स्थानीय संस्कृति, परंपरा और हुनर की पहचान हैं। इन उत्पादों को खरीदकर हम न केवल स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि उनसे जुड़ी महिलाओं की आजीविका को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में भी योगदान देते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों का समय स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण अवसर है। प्रदेशवासी त्योहारों पर उपहार एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीद में स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक प्राथमिकता दें। हमारे द्वारा स्थानीय स्तर पर तैयार किए गए उत्पाद की प्रत्येक खरीद किसी परिवार की आय बढ़ाने, किसी महिला के स्वरोजगार को मजबूती देने और राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में सहायक बनती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 'वोकल फॉर लोकल' अभियान ने देश में स्थानीय उत्पादों के प्रति एक नया विश्वास पैदा किया है। राज्य सरकार भी महिला स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों के



उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि इस त्योहारी सीजन में स्थानीय उत्पाद खरीदें, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें और 'वोकल फॉर लोकल' को जन-अभियान बनाने में अपना योगदान दें। स्थानीय उत्पादों को अपनाने से ही आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और अधिक मजबूती मिलेगी।

ओएलएक्स पर कार बेचने के नाम पर पुलिसकर्मी के बेटे से 46 हजार ठगे

देहरादून । साइबर ठगों ने एक पुलिसकर्मी के नाबालिग बेटे को ओएलएक्स पर सस्ती कार का झांसा दे 46,500 रुपये ठगा लिए। नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने सोमवार को पीड़ित हेड कांस्टेबल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल नवीन सिंह ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनके 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले बेटे को स्कूल के काम के लिए मोबाइल दिया गया था। इसी दौरान ओएलएक्स पर एक आल्टो कार का विज्ञापन देखकर उसने संपर्क किया। आरोपियों ने फर्जी आरसी और शपथ पत्र भेजकर नाबालिग को झांसे में लिया और यूपीआई के माध्यम से कुल 46,500 रुपये ट्रांसफर करवा लिए। ठगी की मुख्य घटना बीते एक जून 2026 की है, जब नवीन सिंह अपनी ड्यूटी पर थे।

वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल एवं निर्यात संवर्धन को लेकर मुख्य सचिव ने ली जिलाधिकारियों के साथ बैठक

देहरादून । मुख्य सचिव आनन्द बर्धन ने मंगलवार को सचिवालय में वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल तथा उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी जनपदों को अपने स्थानीय उत्पादों, संस्कृति, परंपराओं और विशिष्ट मेलों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक जनपद अपने किसी एक विशिष्ट पर्व अथवा मेले को वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल के रूप में

विकसित करे। इसके लिए प्रत्येक जिले का वार्षिक इवेंट कैलेंडर तैयार किया जाए। उन्होंने स्थानीय स्टेकहोल्डर्स की भागीदारी सुनिश्चित की जाने पर जोर दिया। कहा कि ऐसे आयोजनों में उत्तराखण्ड के प्रवासी एवं नॉन-रेजिडेंट उत्तराखंडियों को भी जोड़ा जाए, ताकि राज्य के स्थानीय उत्पादों और सांस्कृतिक विरासत को देश-दुनिया तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि मेलों एवं उत्सवों को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया जाना जरूरी है, ताकि आने वाले वर्षों में उनकी स्थायी पहचान और ब्रांड वैल्यू विकसित हो सके।

मुख्य सचिव ने चमोली के रम्माण

फेस्टिवल को बड़े स्तर पर आयोजित करने एवं उत्तरकाशी के बटर फेस्टिवल जैसे यूनिक आयोजनों को भी व्यापक स्तर पर बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया। उन्होंने पौड़ी और चमोली में आयोजित होने वाले शरदोत्सव, हरिद्वार महोत्सव, नैनीताल विंटर कार्निवल और मसूरी विंटर कार्निवल को भी और अधिक आकर्षक एवं व्यवस्थित रूप से आयोजित करने पर जोर दिया गया। उन्होंने चम्पावत में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल एंगलिंग मीट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने तथा उत्तरायणी मेले में एडवेंचर गतिविधियों को

बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने जनपदवार निर्यात की संभावनाओं की समीक्षा भी की। उन्होंने प्रत्येक जनपद के लिए बेसलाइन डेटा तैयार करने और उसके आधार पर निर्यात संवर्धन की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने निर्यात संवर्धन के लिए प्रमुख सचिव नियोजन की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति गठित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा इस समिति में सचिव उद्योग, सचिव वन, सचिव आयुष सहित अन्य हितधारकों को शामिल किया जाए।

मुख्य सचिव ने स्थानीय उत्पादों की

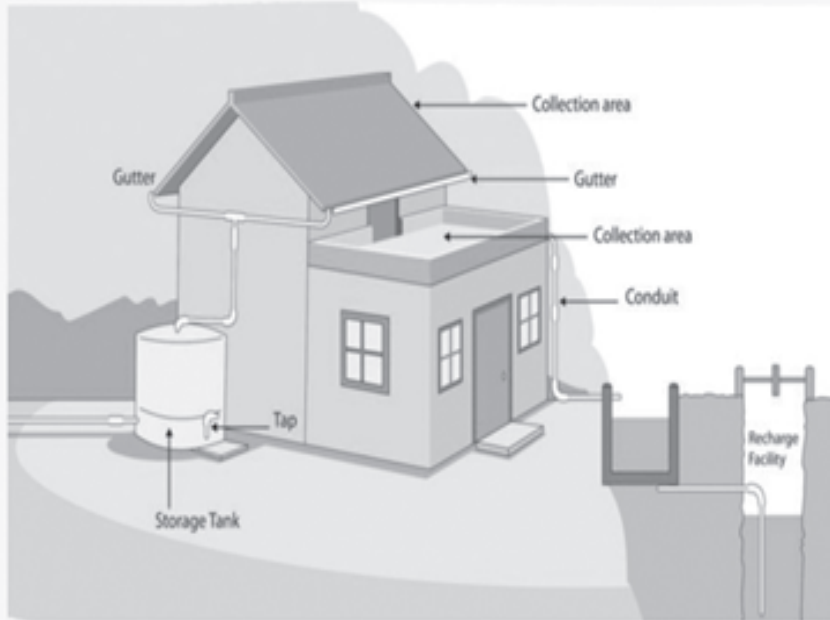
पहचान कर उनकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, गुणवत्ता, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संभावनाओं का अधिकतम उपयोग करने तथा प्रत्येक जनपद के उत्पादों की यूएसपी विकसित किए जाने की दिशा में कार्य किया जाए। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से कहा कि विभिन्न जनपदों के सफल प्रयोगों और अनुभवों को आपस में साझा किया जाए, ताकि एक जनपद की अच्छी पहल को दूसरे जनपद में भी लागू किया जा सके।

RAIN WATER HARVESTING

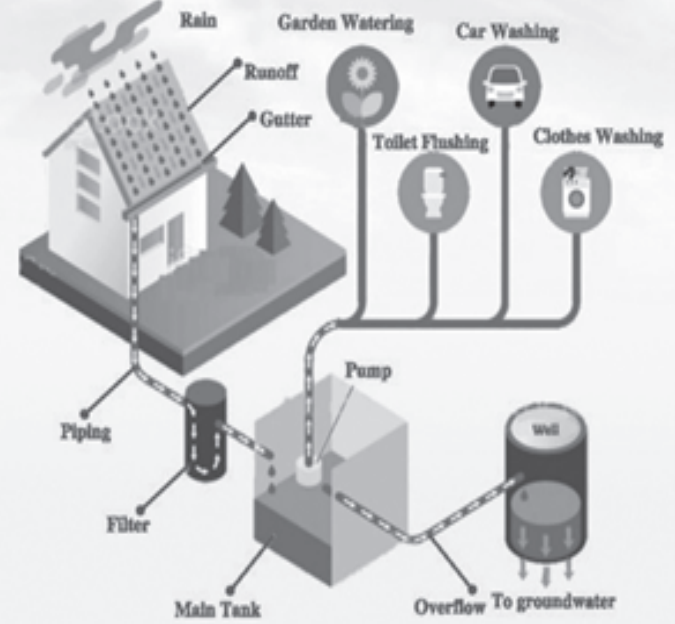
रेन वाटर हार्वेस्टिंग

वर्षा जल संग्रहण के लाभ:-

- ❖ मानसून सीजन से अतिरिक्त सीजन्स में जल की उपलब्धता बनाये रखने में।
- ❖ सूखे की समस्या से निपटने में।
- ❖ भूमिगत जल की स्थिति को सुधारन में।
- ❖ सस्टेनेबल वॉटर सप्लाई की ओर एक कदम
- ❖ शहर की जल आपूर्ति पर बढ़ते दबाव को घटाने में
- ❖ सामूहिक रूप से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को उपयोग में लाने से शहर के ड्रेनेज सिस्टम पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सकता है, जिससे बाढ़ एवं भू-क्षरण की समस्या का नियंत्रण किया जा सकता है।



बादल के गुब्बारों
की बूंद-बूंद संभालो,
कुदरत की इस दौलत का
तुम लाभ उठा लो



रख-रखाव के तरीके:-

- ❖ छत की सफाई हमेशा करें।
- ❖ रेन सेपरेटर का कैप तभी खोलें जब वर्षा बंद हो जाये। वर्षा जल के बह जाने के बाद उसे बंद कर दें।
- ❖ फिल्टर को हमेशा साफ रखें।
- ❖ टैंक की सफाई हर 06 माह के अंतराल पर जरूरी है।

... Save it for another day!



DID YOU KNOW

ONLY 8% OF FALL RAINWATER IS COLLECTED IN INDIA

For More Information Contact Your Architector visit : <http://mddaonline.in/>



MDDA, DEHRADUN

(Mussoorie Dehradun Development Authority, Dehradun)

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून

(An ISO Certified Authority)

प्रकृति, नारीत्व, भक्ति और लोकरंजन का अपूर्व पर्व कजरी तीज

—अशोक 'प्रवृद्ध'

भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाने वाली कजरी तीज सनातनी संस्कृति की वह पावन वेला है, जो प्रकृति, नारीत्व, भक्ति और लोकरंजन के अपूर्व समन्वय को रेखांकित करती है। यह केवल एक लोकपर्व नहीं, अपितु श्रुति, स्मृति, पुराणों की उस अविच्छिन्न परंपरा का जीवंत विग्रह है, जो आदि-शक्ति के महात्म्य और सृष्टि के सृजनात्मक प्रवाह को अक्षुण्ण बनाए हुए है। कजरी तीज का दार्शनिक मूलाधार शक्ति तत्व और प्रकृति तत्व का द्वैत संबंध है। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष (ब्रह्म) अकर्ता है और प्रकृति (शक्ति) जगत की कर्त्री है। भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को मनाया जाने वाला यह पर्व उसी मूल प्रकृति के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की आराधना का महापर्व है। कजली या कजरी शब्द संस्कृत के कज्जल शब्द से व्युत्पन्न है। कज्जल का अर्थ है— श्यामवर्ण या सघन मेघ। दार्शनिक दृष्टि से यह श्यामवर्ण सृष्टि के प्रलयकालीन गर्भाशय का प्रतीक है, जहां से नव सृष्टि की अंकुरण प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तंत्र शास्त्रों में माँ आदि शक्ति को काली या श्यामा कहा गया है—

या देवी सर्वभूतेषु शक्ति-रूपेण संस्थिता।

यह श्यामवर्ण उसी अनंत, अगाध और अनादि ऊर्जा का संवाहक है। सनातन काल गणना में तृतीया तिथि का विशेष महत्व है। यह तिथि अग्नि तत्व और गौरी तत्व की अधिष्ठात्री मानी जाती है। वराह पुराण के अनुसार तृतीया तिथि माँ गौरी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इसी तिथि को उनकी तपस्या पूर्णता को प्राप्त हुई थी। कजरी तीज इसी गौरी तत्व के भौतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष का संधिकाल है। कजरी तीज का उल्लेख विभिन्न पुराणों और संहिताओं में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्राप्त होता है। यह पर्व कजली व्रत, सातोड़ी तीज, और बुढ़ी तीज के नामों से भी जाना जाता है, परंतु इसका मूल महात्म्य उमा-महेश्वर के दिव्य मिलन पर आधारित है। शिवपुराण के रुद्रसंहिता पार्वती खंड में देवी पार्वती के



कठिन तप का विस्तृत वर्णन है। सती के आत्मदाह के पश्चात जब देवी ने हिमवान के गृह में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया, तब उन्होंने बाल्यकाल से ही भगवान शिव को पति रूप में वरण करने का संकल्प लिया। पौराणिक ग्रन्थों के अनुसार भाद्रपद के इस मास में देवी ने निराहार, निर्जला रहकर तपस्या की थी। यद्यपि कुछ ग्रंथों में शुक्ल तृतीया (हरितालिका) और कुछ में कृष्ण तृतीया (कजली) का उल्लेख सघन साधना के विभिन्न चरणों के रूप में आता है। कजरी तीज मूलतः उस विरह अवस्था की समाप्ति का सूचक है, जहां मेघों की श्यामलता (कजली) देवी के अंतर्मन की व्याकुलता और शिव की अनन्यता को एकाकार करती है। स्कन्दपुराण के अंतर्गत उत्कल खंड और काशी खंड में कजली वन का उल्लेख मिलता है। पौराणिक भूगोल के अनुसार विन्ध्याचल और मध्य भारत के सघन वनों को प्राचीन काल में कजली वन कहा जाता था। इस वन में माँ विन्ध्यवासिनी, जो साक्षात् आदि शक्ति और कृष्ण की आद्या शक्ति हैं, का

वास माना गया है। मान्यता है कि इसी कजली वन में महर्षियों ने सामगान की ऋचाओं का लोक शैलियों में रूपांतरण किया, जिसे कालांतर में कजली गायन कहा गया। इस प्रकार यह पर्व भौगोलिक रूप से आर्यावर्त की रीढ़ (विन्ध्य क्षेत्र) से संप्रकृत है। भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में व्रतों की महिमा के अंतर्गत श्रीकृष्ण युधिष्ठिर को तृतीया व्रत की महत्ता समझाते हुए कहते हैं—

हे कुन्तीनन्दन! भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो तृतीया है, वह स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इस दिन जो नारी सुवासित द्रव्यों से युक्त मिट्टी के पिंड बनाकर, शिव-पार्वती की अर्चना करती है, वह कभी वैधव्य को प्राप्त नहीं होती। कजरी तीज का अनुष्ठान केवल बाह्य आडंबर नहीं, वरन पूर्णतः वैज्ञानिक और यौगिक क्रियाओं पर आधारित है। इस पर्व के मुख्य आनुष्ठानिक अंगों का अपना शास्त्रीय विश्लेषण, लौकिक व भौतिक महत्व है। नीमड़ी माता का पूजन का आध्यात्मिक महत्व है— शीतलता, आरोग्य एवं प्रकृति रक्षा। नीम की कड़वाहट विकारों का शमन करती है। पिंड-पूजन (सत्तू अर्पण) अन्नपूर्णा तत्व

की वंदना है, सत्तू (चना, जौ, गेहूँ) चातुर्मास में सुपाच्य और ऊर्जा प्रदायक है। कजली गायन विरह से मिलन की ओर की अंतर्गता है, वर्षा ऋतु में वात-पित्त-कफ के संतुलन हेतु नाद योग। चंद्रोदय को अर्घ्य मन के कारक चंद्र की शांति रात्रिकालीन अर्घ्य से मानसिक उद्वेग का शमन होता है। कजरी तीज के दिन स्त्रियां तालाब या जलस्रोत के किनारे नीम की डाली रोपकर नीमड़ी माता के रूप में उसकी पूजा करती हैं। आयुर्वेद के प्रकांड ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में नीम को सर्व रोग निवारिणी कहा गया है। चातुर्मास (वर्षा ऋतु) में संक्रामक रोगों का प्रकोप सर्वाधिक होता है। नीम की पूजा और उसके स्पर्श से वातावरण परिशुद्ध होता है। आध्यात्मिक रूप से, नीम कड़वाहट में छिपे अमृत का प्रतीक है— ठीक वैसे ही जैसे जीवन के संघर्षों को झेलकर ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कजरी तीज भारतीय समाज की समरसता का अनुपम दृष्ट्यंत है। आषाढ़ और सावन के महीनों में कृषि कार्य (धान की रोपाई आदि) में व्यस्त

रहने के बाद, भाद्रपद में जब मेघ मंद होने लगते हैं, तब ग्रामीण संस्कृति इस पर्व के माध्यम से थोड़ा विश्राम लेती है। यह श्रम के उत्सव में बदलने की कला है। इस पर्व पर नवविवाहित कन्याओं को उनके पीहर अर्थात् मातृ गृह बुलाने की प्राचीन परंपरा है, जिसे सिंजारा या तीज का लिवा लाना कहा जाता है। यह कन्या के मानसिक संबल और मायके के प्रति उसके शाश्वत सरोकारों को जीवंत रखता है। भारतीय समाज विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश की एक अत्यंत भावपूर्ण, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा है। सरल शब्दों में, इसका अर्थ है विवाहित बेटी को उसके मायके (पीहर) के किसी पुरुष सदस्य, जैसे भाई या पिता द्वारा आदरपूर्वक ससुराल से मायके वापस ले आना। कजरी केवल लोकगीत नहीं है। यह शास्त्रीय संगीत की उप शास्त्रीय विधा का रूप ले चुकी है। मिर्जापुर और बनारस घराने की कजरी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसके स्वरों में जो विरह, प्रतीक्षा और अंततः मिलन का उल्लास है, वह जीवात्मा का परमात्मा के प्रति मिलन की व्याकुलता का ही संगीतमय प्रतिरूप है। कजरी तीज केवल एक तिथि विशेष का व्रत नहीं है, अपितु यह सनातन संस्कृति के उस शाश्वत सत्य का उद्घोष है जो सिखाता है कि प्रकृति और नारी एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक इस पृथ्वी पर मेघ श्यामवर्ण धारण कर बरसते रहेंगे, जब तक वनस्पतियां (नीम) मानव जाति को आरोग्यता देती रहेंगी, और जब तक नारीत्व अपनी आंतरिक शक्ति (पार्वती तत्व) से संपूर्ण जगत को अभिसिंचित करता रहेगा, तब तक कजरी तीज जैसे पर्व प्रासंगिक, वंदनीय और अक्षुण्ण बने रहेंगे। यह पर्व हमें अपनी जड़ों (प्रकृति) की ओर लौटने, संबंधों की शुचिता बनाए रखने और जीवन को उत्सवधर्मी बनाने का सनातन संदेश देता है।

विपक्ष ने सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध किया

एस. सुनील

पूरी प्रक्रिया में कुछ भी ऐसा नहीं था, जिसका विरोध किया जाना चाहिए। परंतु विपक्ष ने सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध किया इसके पीछे एक कारण यह भी था कि विपक्षी पार्टियां लगभग सारे समय छात्रों के आंदोलन से दूर रही थीं। जब उनको लगा कि छात्रों के अंदर आक्रोश है तब तक देर हो गई थी। उसी की भरपाई करने के लिए विपक्षी पार्टियां ओवरटाइम कर रही हैं। संत कवि रहीम ने लिखा है, 'क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। का रहीमन हरि घटयो, जो भृगु मारी लात'। इसका अर्थ है कि क्षमा करना बड़े लोगों की शोभा है। उन्होंने अपने इस दोहे में एक प्राचीन हिंदू कथा का हवाला दिया है, जिसके मुताबिक भृगु ऋषि एक बार भगवान विष्णु से मिलने गए। उस समय भगवान विश्राम कर रहे थे। इससे नाराज भृगु ने उनकी छाती पर लात मार दिया। इसके बावजूद निद्रा से उठे भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और उनकी बात सुनी। कहते हैं कि इससे नाराज होकर मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गई

थीं और उन्हें खोजते हुए विष्णु भगवान भी पृथ्वी पर आए। तिरूमाला की पहाड़ियों में उनको मां लक्ष्मी मिलीं। वहीं तिरुपति के रूप में भगवान विराजमान हैं, जो आज एक प्रसिद्ध तीर्थ है। बहरहाल, रहीम का दोहा और यह प्रसंग बताने का उद्देश्य यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़प्पन दिखाया है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया, जिसमें अपनी पीड़ा भी जाहिर की लेकिन साथ ही उनके और उनकी मां के लिए अपमानजनक शब्द कहने वाले छात्रों और युवाओं को 'गुमराह बच्चे' बताते हुए उनको माफ भी कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे नहीं चाहते हैं कि बच्चों को पेशानी हो और उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ें। इसलिए उन्होंने खुद भी बच्चों को माफ किया और समाज से भी अपील करते हुए कहा कि वे बच्चों के प्रति ऐसा ही सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाएं। प्रधानमंत्री ने एक अभिभावक के रूप में बच्चों के भविष्य की चिंता जताई और उन्हें

सही राह दिखाने की आवश्यकता भी बताई। प्रधानमंत्री के वीडियो का एक पहलू तो यह है, जिसमें वे एक अभिभावक के तौर पर बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए उनको माफ कर रहे हैं और सही रास्ते पर लाने की आवश्यकता बता रहे हैं, जबकि दूसरा पहलू एक संवेदनशील प्रधानमंत्री के तौर पर यह स्वीकार करने का है वे समाज में विद्यमान आक्रोश को समझ रहे हैं। यह साधारण बात नहीं है कि प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि समाज में आक्रोश है। प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित किया कि इस आक्रोश की अभिव्यक्ति के तौर पर छात्रों और युवाओं ने जंतर मंतर पर जो कुछ कहा या किया इसके लिए उनको सजा न मिले, बल्कि उनको यह संदेश जाए कि सरकार ने उनके सरोकारों को समझा है। तभी प्रदर्शनकारी छात्रों से किए गए वादे के मुताबिक सरकार ने हर जगह मुकदमे वापस किए हैं। छात्रों पर दर्ज एफआईआर रद्द की गई है। प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी के लोगों को भी यह संदेश दिया कि वे सोशल मीडिया में या समाज

में सार्वजनिक जगहों पर बच्चों को सजा देने या पेशान करने वाला कोई काम नहीं करें। इस पहल से छात्रों व युवाओं का विश्वास बहाल होगा। ध्यान रहे भारतीय संस्कृति में क्षमा को बहुत महत्व दिया गया है। प्रधानमंत्री की ओर से छात्रों को क्षमा करने का भाव दिखाने के बाद नोएडा की एक छात्रा का वीडियो वायरल हुआ, जिसने जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे थे। उस नाबालिग लड़की ने अपनी बातों पर अफसोस जताया।

रलानि का भाव उसकी बातों से स्पष्ट झलक रहा था। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की पहल के बाद ऐसा भाव लाखों युवाओं के मन में आया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले शुक्रवार की देर रात को जारी वीडियो में कहा हो कि वे समाज में विद्यमान आक्रोश को समझ रहे हैं। लेकिन असल में वे इसे पहले ही समझ गए थे और तभी नीतिगत पहल का ऐलान कर दिया था ताकि लोगों

का आक्रोश समाप्त हो और व्यवस्था में विश्वास बहाल हो। उन्होंने इसकी शुरुआत गुरुवार, 23 जुलाई को ही कर दी थी, जिस दिन पेपर लीक रोकने के लिए कठोर सजा के प्रावधान वाला बिल लाने की घोषणा की थी। उसके तुरंत बाद 'पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रीवेशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026' को कैबिनेट ने मंजूरी दी। सोमवार को यह बिल लोकसभा में पेश किया गया। मंगलवार और बुधवार की चर्चा के बाद इसे लोकसभा ने मंजूरी दी और गुरुवार को राज्यसभा से बिल मंजूर हो गया। यह संयोग है कि गुरुवार की शाम को ही प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। छात्रों, युवाओं और उनके अभिभावकों के सरोकारों को समझते हुए प्रधानमंत्री ने नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त कमेट्री का गठन किया। यह कमेट्री परीक्षा प्रणाली की कमियों को पहचान कर उसमें सुधार के सुझाव देगी।



मा० पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

सार्वजनिक सूचना



सर्वसाधारण/आम जनमानस को सूचित किया जाता है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्रान्तर्गत यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा आवासीय / गैर आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि क्रय की जा रही हो तो कृपया भूमि क्रय करने से पूर्व प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी निम्न सूचनाओं/जानकारी का संज्ञान अवश्य लिया जाये :-

- ◆ प्राधिकरण के कार्य क्षेत्रान्तर्गत भूमि क्रय करने से पूर्व कृपया। एम.डी.डी.ए. कार्यालय से भूमि के भू-उपयोग की जानकारी अवश्य रूप से ली जाये। इस हेतु केता को कय की जाने वाली भूमि/भूखण्ड का वास्तुविद / ड्राफ्टमैन द्वारा बनाया गया की-प्लान तथा भू-खण्ड के गूगल को-ऑर्डिनेट्स/भू-खण्ड की गूगल लोकेशन प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- ◆ अवैध प्लॉटिंगों पर कय किये गये भू-खण्ड पर एम.डी.डी.ए. द्वारा मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जाता है।
- ◆ मा. उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के आदेश तथा भवन उपविधि के अनुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज नदी के क्षेत्र से 30 मी० की दूरी के उपरान्त ही भूमि कय की जाये।
- ◆ प्राधिकरण से बिना स्वीकृति/अनुमति से की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर भू-खण्ड कदापि कय न किया जाये। यदि सूचित होने के बावजूद भी भू-खण्ड कय किया जाता है तथा एम.डी.डी.ए. द्वारा भवन उपविधि के अनुसार प्रश्नगत अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध सील अथवा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी केता की रहेगी। एम.डी.डी.ए. द्वारा विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत की गयी अवैध प्लॉटिंगों की भूमि के सम्बन्ध में सूचना/जानकारी एम.डी.डी.ए. की ऑफिशियल वेबसाइट एमडीडीएओनलाइन-इन पर उपलब्ध है।
- ◆ जनहित में यह भी सूचित किया जाता है कि भूमि/भू-खण्ड कय करने से पूर्व कय की जाने वाली भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेजों का परीक्षण/सजरे के अनुसार भू-खण्ड खसरा न० की स्थिति स्पष्ट करने/कय की जाने वाली भूमि में किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद होने अथवा न 1 न होने/कय की जाने वाली भूमि के रकबे में सरकारी भूमि सम्मिलित होने के सम्बन्ध में कृपया राजस्व विभाग से गली-माति परीक्षण कराया जाये।
- ◆ प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी उक्त सूचनाओं / जानकारी के कम में कय की गयी भूमि/भू-खण्ड का एम.डी.डी.ए. कार्यालय से नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरान्त ही मोके पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।
- ◆ क्रय की जाने वाली भूमि/भू-खण्ड के सम्बन्ध में भूमि विक्रेता से भूमि/भू-खण्ड का प्राधिकरण से स्वीकृत ले-आउट/तलपट मानचित्र की जानकारी प्राप्त की जाये कि जो भू-खण्ड केता द्वारा बिक्रेता से कय किया जा रहा है क्या वह भू-खण्ड स्वीकृत ले-आउट मानचित्र का भू-खण्ड का माग है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में भूमि विक्रेता से स्वीकृत ले-आउट मानचित्र/मानचित्र संख्या की जानकारी प्राप्त करते हुए उसका सत्यापन एम.डी.डी.ए. कार्यालय से अवश्य रूप से किया जाये।

उक्त सूचना/जानकारी जनहित में जारी की जाती है।

“आज्ञा से
उपाध्यक्ष
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण”
देहरादून।



मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण लाया है

देहरादून शहर में पहले आओं पहले पाओं स्कीम के तहत
अपने **घर** का सपना पूरा करने का एक सुनेहरा मौका।

एम.डी.डी.ए. की ट्रांसपोर्ट नगर फेज-2, आई.एस.बी.टी. एवं आमवाला तरला, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून की आवसीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित आय वर्ग के लोगों हेतु पंजीकरण प्रारम्भ:-

HIG | MIG | STUDIO APARTMENT | L.I.G.



क्र. स.	फ्लैटों की श्रेणी	अनुमानित कीमत रु लाख में।	पंजीकरण धनराशि रु लाख में।	फ्लैट का अनुमानित सुपर एरिया (वर्ग फीट)	फ्लैटों की संख्या	क्र. स.	फ्लैटों की श्रेणी	अनुमानित कीमत रु लाख में।	पंजीकरण धनराशि रु लाख में।	फ्लैट का अनुमानित सुपर एरिया (वर्ग फीट)	फ्लैटों की संख्या
1.	अल्प आय वर्ग (LIG) आलयम, सहस्त्रधारा रोड	22.90	2.30	582.82	60	5.	स्टूडियो अपार्टमेंट आलयम, सहस्त्रधारा रोड	32.29	3.23	798.18	48
2.	अल्प आय वर्ग (LIG 'C' Block) आलयम, सहस्त्रधारा रोड	23.29	2.32	582.82	16	6.	अल्प आय वर्ग (LIG) ट्रांसपोर्ट नगर, फेज-2	19.90	2.00	453.53	97
3.	मध्यम आय वर्ग (MIG) आलयम, सहस्त्रधारा रोड	65.85	6.59	1503.40	112	7.	मध्यम आय वर्ग (MIG) ट्रांसपोर्ट नगर, फेज-2	49.50	4.95	1090	27
4.	उच्च आय वर्ग (HIG) आलयम, सहस्त्रधारा रोड	75.64	7.57	1877.83	112	8.	उच्च आय वर्ग (HIG) आई.एस.बी.टी.	71.50	7.15	1954	130

विशेष छूट :-

- उक्त भवनों में एक मुश्त धनराशि जमा किये जाने पर 02 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
- यदि कोई महिला/सिनियर सिटिजन/दिव्यांग इस हेतु आवेदन करे तो उनको 01 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट उनको पूर्ववत 02 प्रतिशत की छूट प्रदान करने के उपरान्त अवशेष देय धनराशि प्रदान की जायेगी।

आलयम आवसीय योजना
की जानकारी हेतु
मो. **8006409136**



आई.एस.बी.टी./ट्रांसपोर्ट नगर
आवसीय योजना की जानकारी हेतु
मो. **9193639595**

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

सहस्त्रधारा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, देहरादून। फोन : 0135-663150

E mail: info.mdda@mddaonline.in Website : www.mddaonline.in

पंजीकरण फॉर्म प्राधिकरण के साइट ऑफिस, कार्यालय व नीचे दिये गए बैंक की शाखाओं में भी उपलब्ध है।

देवभूमि की पवित्रता और मूल स्वरूप को बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता



हरिद्वार । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को श्री ब्रह्म निवास आश्रम, सप्तसरोवर रोड, भूपतवाला में पूज्य सतगुरु लाल दास महाराज के 51वाँ निर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूज्य सतगुरु लाल दास महाराज ने अपने जीवन में आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देते हुए समाज को सेवा, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने भक्ति को जन जन तक

पहुँचाया है। उनकी वाणी में अद्भुत शक्ति थी और दृष्टि में भगवान बुद्ध के समान असीम करुणा थी। पूज्य सतगुरु ने समाज को जोड़ने का काम किया। उन्होंने जीवन भर यही सिखाया कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संतों का सानिध्य और सतगुरु की कृपा मिलना सौभाग्य की बात है। हमारे संत समाज ने हमेशा धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए बढ़-चढ़कर योगदान दिया

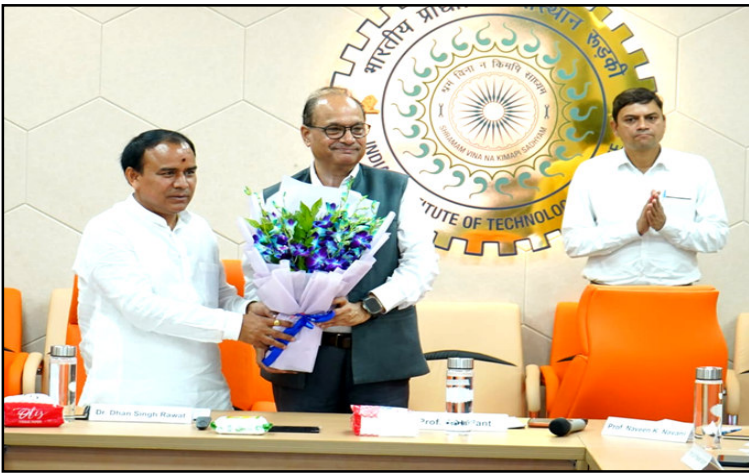
है। उनके मार्गदर्शन से समाज को धर्म और संस्कृति के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। भारत की महान संस्कृति हमें सिखाती है कि कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, हमें अच्छे समाज के निर्माण और विकास को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सनातन धार्मिक संस्कृति के पुनर्जागरण का स्वर्णिम काल चल रहा है। अयोध्या में भगवान श्रीराम मंदिर, काशी कॉरिडोर और उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर जैसे कार्यों के साथ उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 2013 की आपदा में क्षतिग्रस्त केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और प्रेरणा से किया गया है। मंदिर माला मिशन के तहत प्रदेश के विभिन्न मंदिरों का पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। रोपवे बनने से कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण दुर्गम तीर्थ स्थलों तक पहुँचने में श्रद्धालुओं को सुविधा

मिलेगी और बुजुर्ग तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा अधिक सुगम होगी। हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर, ऋषिकेश कॉरिडोर, आस्था पथ तथा शारदा और यमुना तटों के विकास जैसे कार्य भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की देवभूमि का मूल स्वरूप, पवित्रता और सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहना जरूरी है। सरकार का प्रयास है कि देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और आध्यात्मिक वातावरण मिले। अवैध निर्माण तथा देवभूमि की संस्कृति और सामाजिक वातावरण को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में हिंदू अध्ययन केन्द्र बनाया गया है जिसमें धर्म और संस्कृति के साथ ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदार की धरती से कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इस दिशा में धर्म, विकास, नवाचार और ज्ञान के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर एवं देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। संतों और आचार्यों के सानिध्य तथा देश-दुनिया के लोगों की आस्था के साथ देवभूमि के विकास और संरक्षण का यह अभियान निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। इस अवसर

पर श्री सतगुरु चेतनानंद जी भूरी वाले ने कहा कि संस्था द्वारा 57 वर्ष से निरंतर अखंड भोजन करवा रहा है, संस्था गरीबों की सेवा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश में ऐसे नियम एवं कानून लागू किए हैं, जिसका पूरा देश अनुसरण कर रहे है, उनके कुशल नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर हो रहा है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक एवं उपाध्यक्ष आपदा प्रबंधन विनय रोहिल्ला ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरि महाराज, मेयर रुड़की अनीता अग्रवाल, जिलाध्यक्ष भाजपा आशुतोष शर्मा, राज्य मंत्री शोभाराम प्रजापति, ओमप्रकाश जमदग्नि, प्रदेश सह-मीडिया प्रभारी विकास तिवारी, आशु चौधरी, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून प्रमोद डोभाल, एसपी ट्रैफिक निशा यादव, अपर जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट हर गिरी, उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा, सचिव एचआरडीए प्रत्यूष सिंह, साधु संत सहित विभिन्न प्रदेशों से आए भक्तगण मौजूद रहे।

एनईपी के क्रियान्वयन में तेजी लायें विश्वविद्यालय: डॉ. धन सिंह रावत



रूड़की/देहरादून । सूबे में नई शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन को सभी विश्वविद्यालय ठोस व समयबद्ध रोडमैप तैयार करेंगे। साथ ही उच्च शिक्षा को रोजगारपरक, नवाचार आधारित और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिये विश्वविद्यालयों को परंपरागत शिक्षण पद्धतियों के साथ आधुनिक तकनीक एवं उद्योग जगत की आवश्यकताओं के साथ ही भारतीय ज्ञान परम्परा को भी पाठ्यक्रमों में शामिल करना होगा। इसके अलावा परीक्षा प्रणाली व छात्रों के डेटा को सुरक्षित रखने के लिये भी ठोस कदम उठाने होंगे। सूबे के विद्यालयी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज आईआईटी रूड़की में आयोजित 'उत्तराखंड एनईपी कॉन्क्लेव-2026' में बतौर मुख्य अतिथि अपने विचार रखे। 'एनईपी एक्शन प्लान्ट टू इंस्टीट्यूशनल एक्शन: उत्तराखंड हायर एजुकेशन रोडमैप' थीम पर आयोजित राज्य स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला को सम्बोधित करते हुये डॉ. रावत ने कहा कि नई शिक्षा नीति-2020 के शत-प्रतिशत प्रावधानों को धरातल पर उतारने के लिये सभी विश्वविद्यालयों को स्पष्ट व समयबद्ध रोडमैप तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ-साथ कौशल, नवाचार और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिये विश्वविद्यालयों को परंपरागत शिक्षण पद्धतियों के साथ आधुनिक तकनीक एवं उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम संचालित करने होंगे। साथ ही विश्वविद्यालयों में आधुनिक लैब, इनोवेशन

सेंटर, स्टार्टअप एवं इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने होंगे ताकि छात्र-छात्राएं इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। डॉ. रावत ने विश्वविद्यालयों को स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर के उद्योगों के साथ एमओयू कर विद्यार्थियों के लिये इंटरशिप, इंडस्ट्री विजिट, प्रोजेक्ट वर्क, प्रशिक्षण तथा रोजगार व स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने को कहा। उन्होंने उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों को अपडेट करने के साथ ही विद्यार्थियों में उद्यमिता की भावना विकसित करने पर भी विशेष जोर दिया। डॉ. रावत ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ऐसे पाठ्यक्रम और शोध कार्यों को बढ़ावा दें, जिनका सीधा लाभ प्रदेश की अर्थव्यवस्था और स्थानीय युवाओं को मिले। पर्यटन, कृषि, बागवानी, आयुष, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, हिमालयन इकोलॉजी सहित स्थानीय उत्पादों से जुड़े शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी विश्वविद्यालयों को ठोस पहल करनी होगी। इसके अलावा उन्होंने राज्य स्तर पर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की रैंकिंग शुरू करने, विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक एवं शिक्षण के शतप्रतिशत रिक्त पदों को भरने, पुरातन छात्रों का डाटा तैयार करने, छात्रावासों का सुरक्षा ऑडिट करने, पेपर लीक एवं छात्रों के डाटा को सुरक्षित रखने के साथ ही छात्रों से निरंतर संवाद करने को भी कहा। कार्यशाला में कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डी.एस. रावत ने एनईपी-2020 के क्रियान्वयन, चुनौतियों एवं

गुणवत्ता विषय पर प्रस्तुतिकरण दिया। वहीं आईआईटी रूड़की के निदेशक प्रो. के.के. पंत ने ज्ञान में मेंटरिंग एवं क्षमता निर्माण, संस्थागत सहयोग तथा हब एंड स्पोक मॉडल की संभावनाओं पर अपने विचार रखे।

सचिव उच्च शिक्षा बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने वर्ष 2028 तक एनईपी-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उच्च शिक्षा विभाग का रोडमैप एवं एजेंडा प्रस्तुत किया। इसके अलावा दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रमाकांत पाण्डेय तथा ग्राफिक एरा डीमंड विश्वविद्यालय के महानिदेशक प्रो. अमित आर. भट्ट ने इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, रिसर्च एवं इनोवेशन तथा पाठ्यक्रम में आवश्यक अपडेट को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया। इसी क्रम में एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. प्रकाश सिंह, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के कुलपति प्रो. एस.एस. बिष्ट तथा एसजीआरआर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. के. प्राथापन ने नए इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, इनक्यूबेशन सेंटर एवं मेगा एजुकेशन हब की संभावनाओं पर प्रस्तुतिकरण दिया।

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नवीन चन्द्र लोहनी तथा श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अम्बरीश महाजन ने यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं विदेशी संस्थानों के साथ शैक्षणिक सहयोग विषय पर अपने विचार रखे। वहीं तकनीकी विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. तृप्ता ठाकुर, एच.एन.बी. चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. भानु दुग्गल तथा जी.बी. पंत कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. शिवेन्द्र कश्यप ने कौशल आधारित शिक्षा, इंटरशिप योजना, टेक-रेडी वर्कफोर्स तथा कृषि क्षेत्र की प्यूचर रेडीनेस पर प्रस्तुतिकरण दिया। इस अवसर पर आईआईएम लखनऊ के एंटरप्राइज इनक्यूबेशन सेंटर के एचओडी बिजनेस डेवलपमेंट आदित्य प्रसाद ने उत्तराखंड में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने एवं नए स्टार्टअप की स्थापना को लेकर अपना प्रस्तुतिकरण दिया। उनकी टीम में प्रोजेक्ट मैनेजर आदित्य प्रधान, सुधांशु एवं दीपक कुमार भी उपस्थित रहे।

वाटर हार्वेस्टिंग कार्य का पालिकाध्यक्ष और डीएम ने किया शुभारंभ

हरिद्वार । शिवालिक नगर पालिका वार्ड 13 जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में



पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने शुक्रवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के साथ वाटर हार्वेस्टिंग कार्य का शुभारंभ किया। जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर नगर पालिका और जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता को

दोहराया गया। नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि वर्षा जल को संरक्षित करना वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से बारिश के पानी को व्यर्थ बहने से रोककर उसे भूजल रिचार्ज के लिए उपयोग किया जा सकता है। इससे आने वाले समय में जल संकट को कम करने और भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों के साथ-साथ जल संरक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को भी विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में वाटर हार्वेस्टिंग कार्य की शुरुआत एक महत्वपूर्ण पहल है और इससे आमजन को भी जल संरक्षण के लिए प्रेरणा मिलेगी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि वाटर हार्वेस्टिंग आज के समय की आवश्यकता है। वर्षा के पानी को संरक्षित कर भूजल स्तर को रिचार्ज किया जा सकता है और पानी की उपलब्धता को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद मिलती है। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में शुरू किया गया कार्य जल संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक और अनुकरणीय पहल है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक अनीश कुमार द्वारा भगवती प्रिंटर्स, इण्डस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार से छपवाकर ग्रा. बसवाखेड़ी पो. मंगलौर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया।

सम्पादक: अनीश कुमार, मो० 9410553400

ई-मेल: liveskgnews@gmail.com

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र हरिद्वार न्यायालय में ही होगा)

सभी लेखों में सम्पादक की सहमति जरूरी नहीं है।